

‘ओम बिड़ला के ओ.एस.डी. राजीव दत्ता पर लगे मानव तस्करी के आरोपों की जाँच गंभीरता और तीव्रता से करें’

राजस्थान हाई कोर्ट ने निर्देश दिया कि इस मामले में दायर एफ.आई.आर. तथा परिवादों की जाँच ए.डी.जी. (अपराध) दिनेश एम.एन. के निरीक्षण में की जाए

-रेणु मित्तल-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4, अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के ओएसडी राजीव दत्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। अदालत के निर्देशानुसार एफआईआर दर्ज कर ली गई है।

जयपुर राजस्थान उच्च न्यायालय बैच ने कहा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के ओएसडी राजीव दत्ता, अर्चना झाला, दिनेश मुरझानी व वंदिता राणा पुलिस अधीक्षक अजमेर के विरुद्ध अजमेर मजिस्ट्रेट कोर्ट में पेंडिंग मानव तस्करी की शिकायत का अनुसंधान एडीजी क्राइम दिनेश एम.एन. करेंगे एवं याचिकाकर्ता एडवोकेट शेखर मेवाड़ा के विरुद्ध दर्ज एफआईआर का अनुसंधान भी एडीजी क्राइम दिनेश एमएन ही करेंगे।

याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि अजमेर, पाली, बूंदी और कोटा में इस मामले से

■ अदालत ने अपने आदेश में याचिकाकर्ताओं को कानूनी सुरक्षा देते हुए कहा कि इनके खिलाफ पुलिस प्रशासन बलपूर्वक या दण्डात्मक कार्यवाही नहीं कर सकता, जैसे कि उनकी गिरफ्तारी करना इत्यादि. जब तक अदालत ऐसी कार्यवाही करने की अनुमति नहीं देती या याचिकाकर्ता जाँच में सहयोग नहीं करते।

■ याचिकाकर्ताओं की ओर से अदालत में कहा गया कि अजमेर, पाली, बूंदी और कोटा में इस मामले से जुड़ी एफ.आई.आर. व परिवार दायर किया है, परन्तु कोटा में राजनैतिक दबाव के चलते उनकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई।

■ याचिकाकर्ता का कहना है कि कोटा से जयपुर के रास्ते में उनके साथ अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जिसकी भी पुलिस ने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की।

जुड़ी एफ.आई.आर. व परिवार दायर की है, परन्तु कोटा में राजनैतिक दबाव के चलते उनकी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गई। याचिकाकर्ता का कहना है कि कोटा से जयपुर के रास्ते में उनके साथ अंजान व्यक्ति ने मारपीट भी की, जिसकी भी पुलिस ने एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की। अधिवक्ता शेखर मेवाड़ा पर बूंदी में हुए कतिलाना हमले की एफआईआर

दर्ज करने के निर्देश दिए एवं याचिकाकर्ताओं के खिलाफ सभी प्रकार की कानूनी कार्यवाहियों पर रोक लगा दी गई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला के ओएसडी राजीव दत्ता एवं रविंदर गौड़ (आईजी कोटा), गंगा सहाय (डिप्टी एसपी कोटा सिटी), राजेन्द्र कुमार मीणा (एसपी बूंदी), रमेश आर्य (एसएचओ सदर बूंदी), सुनील खटाना व अन्य लोगों के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कार्यवाही करने का आदेश दिया।

निम्न याचिकाओं की तरफ से अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के अध्यक्ष महेन्द्र शांडिल्य ने न्यायालय को बताया कि ऊपर बताए गए व्यक्तियों के खिलाफ मानव तस्करी में परिवार अनुसंधान में लंबित है तथा उच्च न्यायालय ने एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। अदालत के आदेश के अनुसार, “पक्षकारों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने के बाद, न्यायालय में उपस्थित अधिकारी (दिनेश एम.एन.) द्वारा दी (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

एसआई भर्ती पेपर लीक में याचिकाकर्ता की बहस पूरी हुई

जयपुर, 4 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट में एसआई भर्ती-2021 पेपर लीक मामले में याचिकाकर्ता पक्ष से जुड़े सभी वकीलों की बहस पूरी हो गई है। अदालत ने मामले में राज्य सरकार को पक्ष रखने के लिए पांच अगस्त का समय दिया है। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश कैलाश चन्द व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं की ओर से ओपी

■ अब सुनवाई 5 अगस्त को।

सोलंकी और हरेंद्र नील ने अदालत को बताया कि याचिकाकर्ता ने भर्ती को रद्द करने की गुहार करते हुए याचिका दायर की है। याचिका में भर्ती को लेकर राज्य सरकार कोई निर्णय ले, ऐसी प्रार्थना नहीं की गई है। ऐसे में राज्य सरकार की ओर से भर्ती रद्द नहीं करने का निर्णय लेने के आधार पर ही याचिका सारहीन नहीं हो जाती है। याचिकाकर्ता की ओर से बहस पूरी करने के बाद अदालती समय पूरा होने पर अदालत ने मामले की सुनवाई 5 अगस्त को तय की है।

‘अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का मतलब यह नहीं कि आप कुछ भी कह सकते हैं’

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को राहत देने के साथ ही नसीहत भी दी

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राहुल गांधी के खिलाफ सेना पर दिए गए बयान को लेकर दर्ज मानहानि के मुकदमे पर रोक लगा दी, साथ ही यह सवाल भी उठाया कि उन्होंने यह मुद्दा सोशल मीडिया पर क्यों उठाया, संसद में क्यों नहीं?

न्यायमूर्ति दीपाकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने राहुल गांधी को सावधान करते हुए कहा कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे सोशल मीडिया पर उठाने की बजाय संसद में उठाए जाने चाहिए।

बैच ने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ लखनऊ की अदालत में विचारधीन उस क्रिमिनल मानहानि केस में स्टे दे दिया, जो 2022 की “भारत जोड़ो यात्रा” के दौरान भारतीय सेना के बारे में की गई उनकी टिप्पणी

■ सुप्रीम कोर्ट ने सेना के कथित अपमान संबंधी एक केस, जो लखनऊ की एक अदालत में चल रहा था, में कार्यवाही पर स्टे लगा दिया।

■ राहुल पर आरोप था कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने सेना पर टिप्पणी की थी कि चीन के सैनिक अरुणाचल में भारतीय सैनिकों को पीट रहे थे।

■ सुप्रीम कोर्ट ने इस आधार पर राहत दी कि राहुल की टिप्पणी से शिकायतकर्ता प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं है।

■ कोर्ट ने यह भी कहा, यह मुद्दा संसद में उठाया जाना चाहिए।

से सम्बंधित है। गांधी ने कहा था कि “चीनी सैनिक अरुणाचल में भारतीय सैनिकों को पीट रहे हैं।” यह टिप्पणी “लाइन ऑफ़ एक्चुअल कंट्रोल” पर चीनी कार्यवाही को लेकर, केन्द्र सरकार को निशाना बनाते हुये की गई थी। अदालत ने गांधी से यह भी पूछा

कि क्या उनकी टिप्पणी किसी विश्वसनीय सामग्री पर आधारित थी। बैच ने कहा, “आपने यह टिप्पणी सोशल मीडिया पर क्यों की? संसद में क्यों नहीं? आपको कैसे पता चला कि चीन ने 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर कब्जा कर लिया? आपके पास इसका (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

‘रुस से तेल खरीदा तो आयात शुल्क और बढ़ायेंगे’

वाशिंगटन, 04 अगस्त। अमेरिका के राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने सोमवार को धमकी दी है कि यदि भारत ने रुस से तेल खरीदना बंद नहीं किया तो वह भारतीय उत्पादों पर आयात शुल्क और बढ़ा देंगे। ट्रंप ने टुथ सोशल पर एक पोस्ट में लिखा कि भारत को इस बात की चिंता नहीं है कि यूक्रेन में रुस कितने लोगों को मार रहा है। इस कारण, “मैं भारत द्वारा

■ अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप ने फिर भारत को धमकी दी।

अमेरिका को दिये जाने वाले आयात शुल्क में बड़ी बढ़ोतरी करूँगा।” अमेरिकी राष्ट्रपति ने आरोप लगाया कि भारत न सिर्फ रुस से बड़ी मात्रा में तेल खरीद रहा है, बल्कि उसमें से ज्यादातर तेल खुले बाजार में बेचकर भारी मुनाफा कमा रहा है। उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने 01 अगस्त से दुनिया के कई देशों पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने की (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

स्कूल इमारतों की बर्दहाल स्थिति पर सरकार दो सप्ताह में जवाब दे

जयपुर, 4 अगस्त। राजस्थान हाईकोर्ट ने प्रदेश की स्कूलों की इमारतों की बर्दहाल स्थिति और उनमें संसाधनों के अभाव से जुड़े मामले में केंद्र और राज्य सरकार को जवाब पेश करने के लिए दो सप्ताह का समय दिया है। जस्टिस महेन्द्र गोयल और जस्टिस अशोक कुमार जैन की खंडपीठ ने यह आदेश प्रकरण में लिए गए स्वप्रेरित प्रसंज्ञान पर सुनवाई करते हुए दिए।

■ हाई कोर्ट ने प्रकरण के स्वप्रेरित प्रसंज्ञान की सुनवाई 18 अगस्त को तय की।

से मामले में जवाब पेश करने के लिए समय मांगा। इस पर अदालत ने उन्हें दो सप्ताह का समय देते हुए प्रकरण की सुनवाई 18 अगस्त को तय की है। गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने गत 28 जुलाई को प्रदेश की सरकारी स्कूलों के जर्जर भवनों सहित उनमें संसाधनों की कमी को लेकर स्वप्रेरणा से प्रसंज्ञान लिया था। इसके साथ ही अदालत ने मामले में शिक्षा मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, मुख्य सचिव, एस।एस. शिक्षा, प्रमुख बाल कल्याण सचिव और राष्ट्रीय बाल आयोग को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया था। वहीं दूसरी ओर हाईकोर्ट की एक अन्य एकलपीठ ने स्कूल भवनों के (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने पर विचार कर रही है केन्द्र सरकार?

दिन भर सोशल मीडिया पर यह चर्चा आम रही

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 अगस्त। सोशल मीडिया पर इन दिनों इस बात को लेकर एक खास हलचल देखी जा रही है कि केन्द्र सरकार अनुच्छेद 370 हटाय जाने की छठी वर्षगांठ, यानी 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने पर विचार कर रही है।

याद दिला दें कि 5 अगस्त 2019 को केन्द्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म करके, जम्मू-कश्मीर को दो केन्द्र शासित प्रदेशों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख, में बांट दिया था। इसके साथ ही, राज्य की विधानसभा भंग कर दी गई थी तथा वहां की सत्ता एक उप-राज्यपाल के अधीन कर दी गई थी।

केन्द्र पर कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा देने का दबाव भी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी 2023 में केन्द्र सरकार से राज्य का दर्जा जल्द से जल्द तथा “यथाशीघ्र” बहाल करने को कहा था। करीब दस साल के लम्बे इन्तज़ार के बाद, पिछले साल यहां विधानसभा चुनाव हुए, जिसके बाद मध्यमंजरी उमर अब्दुल्ला और कांग्रेस नेता लगातार राज्य का दर्जा

■ चर्चा है कि भारत सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी छवि बेहतर बनाने के लिए यह कदम उठा सकती है।

■ लेकिन, यह भी कहा जा रहा है कि केन्द्र सरकार को भाजपा कार्यकर्ताओं व समर्थकों का इस पर समर्थन शायद ना मिले।

■ भाजपा व मोदी के कई समर्थकों ने कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने पर चिंता जताई और कहा, जल्दबाजी में कोई कदम उठाने की गलती न की जाए।

बहाल करने की मांग कर रहे हैं। हाल के कुछ घटनाक्रमों ने राज्य के दर्जे की लम्बित बहाली की इन अफवाहों को और बल दिया है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 3 अगस्त को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की और इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह ने भी राष्ट्रपति से भेंट की। शाह ने जम्मू-कश्मीर के कुछ नेताओं और भाजपा के प्रदेश प्रमुख के साथ भी मीटिंग की। सूत्रों के अनुसार, प्रधानमंत्री ने मंगलवार को एनडीए सांसदों की भी बैठक बुलाई है। अगर वाकई राज्य का दर्जा बहाल होता है, तो यह कदम प्रधानमंत्री मोदी को वर्तमान गम्भीर चुनौतियों से राहत दिलाने में मदद कर सकता है। ज्ञातव्य है कि हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डॉनल्ड ट्रंप की टैरिफ नीति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे ने सरकार को मुश्किल में डाल दिया है। इसके अलावा, पहलागाम हत्याकांड के बाद पाकिस्तान पर की गई सैन्य कार्रवाई से भी भारत की कूटनीतिक स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ। ऐसा माना जा रहा है कि जम्मू-कश्मीर के राज्य के दर्जे की बहाली से अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय की नजरों में भारत सरकार की स्थिति सुधारने में मदद मिल सकती है। हालांकि, यह कदम भाजपा के समर्थकों को शायद पसंद न आए। सेना के पूर्व अधिकारी और लेखक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

क्या बिहार चुनाव के बाद कोई बम फोड़ सकते हैं चंद्रबाबू नायडू?

लगातार दूसरी बार मोदी सरकार की नीतियों पर विरोध जताया

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-
नई दिल्ली, 4 अगस्त। एक ऐसे कदम के अन्तर्गत, जो एनडीए गठबंधन में दरार को और गहरा कर सकता है, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और तेलुगु देशम पार्टी (टीडीपी) प्रमुख एन. चंद्रबाबू नायडू ने केन्द्र सरकार को कड़े शब्दों में एक पत्र लिखा है। इस पत्र में उन्होंने चिंता जताई है कि अमेरिका द्वारा हाल ही में की गई टैरिफ वृद्धि का आंध्र प्रदेश के झींगा (श्रिम्प) और मत्स्य उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

मोदी सरकार को संबोधित इस पत्र में तटीय क्षेत्रों के उन किसानों के हितों की रक्षा के लिए तत्काल हस्तक्षेप की मांग की गई है, जो समुद्री खाद्य निर्यात पर अत्यधिक निर्भर हैं।

नायडू का यह पत्र ऐसे समय में आया है, जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अमेरिका के इस कदम पर अब तक चुपची साध रखी है, जबकि यह भारत के जलीय कृषि क्षेत्र, विशेष रूप से झींगा

■ अब चंद्रबाबू नायडू ने ट्रंप द्वारा टैरिफ बढ़ाए जाने पर मोदी सरकार को कड़ा पत्र लिखा व आंध्र के मत्स्य उद्योग के लिए गंभीर चिंता जताई।

■ इससे पहले चंद्रबाबू ने बिहार में मतदाता पुनरीक्षण अभियान पर नाराज़गी जताई थी।

■ नायडू के इन कदमों को एनडीए में दरार पड़ने का पूर्व संकेत माना जा रहा है। विशेषज्ञों ने कहा, अगर बिहार चुनाव के नतीजे भाजपा के अनुकूल नहीं आए तो नायडू कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं।

मजबूत रहा एनडीए का गठबंधन अब ढीला हो रहा है। नायडू की यह सतर्क, लेकिन रणनीतिक स्थिति भाजपा एवं विपक्ष दोनों के लिये ही इस बात का संकेत मानी जा रही है कि टीडीपी भविष्य के राजनीतिक समीकरणों को लेकर नए विकल्पों पर विचार कर रही हो सकती है।

आंध्र के मुख्यमंत्री के करीबी सूत्रों का कहना है कि नायडू “राजनीतिक हालात” पर गहरी नजर रखे हुए हैं, खासकर नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों पर। एक शीघ्र टीडीपी पदाधिकारी ने इस संवाददाता को पुष्टि की कि “नायडू, बिहार चुनाव परिणामों के बाद ही, मोदी सरकार को भविष्य में समर्थन देते रहने के बारे में स्पष्ट रुख अपनाएंगे।”

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नायडू के हालिया कदम एनडीए के क्षेत्रीय सहयोगियों में बढ़ती स्वायत्तता की प्रवृत्ति को दर्शाते हैं। हैदराबाद के एक (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

झारखंड के पूर्व मु.मंत्री शिबू सोरेन का निधन



नयी दिल्ली/रांची, 04 अगस्त। पृथक झारखंड आंदोलन के अग्रदूत एवं पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का सोमवार को यहां निधन हो गया। वे 81 वर्ष के थे। सोरेन एक माह से भी अधिक समय से यहां सर गंगा राम अस्पताल में भर्ती थे। उनका किडनी तथा हृदय संबंधी बीमारियों का इलाज चल रहा था। उन्होंने आज सुबह अस्पताल में ही अंतिम सांस ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को यहां गंगाराम अस्पताल जाकर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी और उनके परिजनों से (शेष अंतिम पृष्ठ पर)

विचार बिन्दु

कृत्रिम सुख की बजाये, हमेशा ठोस उपलब्धियों के पीछे समर्पित रहिये। –अब्दुल कलाम

एस.आई.आर. पर रार, आर या पार

आजकल बिहार की मतदाता सूचियों का एस आई आर (विशेष गहन पुनरीक्षण यानि स्पेशल इंटेसिव रिवीजन) चल रहा है। यह पूरे देश में सर्वाधिक चर्चा का विषय बना हुआ है। चुनाव आयोग के अनुसार एस आई आर सभी राज्यों के लिए भी किया जाएगा। अत: देशवासियों के लिए यह समझना आवश्यक है कि यह क्या है और इसका क्या प्रभाव होगा?

चुनाव आयोग के अनुसार एस आई आर, मतदाता सूचियों के शुद्धिकरण की प्रक्रिया है, जिससे मृत, स्थाई रूप से पलायन करने वालों और अयोग्य लोगों के नाम मतदाता सूचियों से हटाए जाते हैं। इसमें, पूरी मतदाता सूची नई बनाई जाती है और प्रत्येक व्यक्ति को नामांकन प्रपत्र भरकर बी एल ओ के पास जमा कराना होता है। बी एल ओ द्वारा इन सबको अपलोड किया जाता है। चुनाव आयोग के अनुसार हर उस व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में होगा जो भारत का नागरिक है और 18 साल से ऊपर है। जिस तरह से धरातल पर बिहार में यह कार्य चल रहा है, उसे देखकर, सभी विपक्षी दल एस आई आर को केवल लोगों के नाम काटने की प्रक्रिया बता रहे हैं।

निर्वाचन आयोग ने प्राप्त प्रपत्रों के आधार पर प्रारूप मतदाता सूचियां का प्रकाशन 1अगस्त 2025 को कर दिया है। 24 जून 2025 को उपलब्ध मतदाता सूचियों में कुल 7.89 करोड़ नाम अंकित थे जबकि ड्राफ्ट मतदाता सूचियों में कुल 7.24 करोड़ नाम हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कुल 65 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए हैं। इस पूरी प्रक्रिया को दलगत राजनीति से ऊपर उठते हुए मतदाता की दृष्टि से देखने की आवश्यकता है।

प्रश्न यह नहीं है कि जिन मतदाताओं के नाम काटे जा रहे हैं, वे किस दल के हैं, अपितु यह कि भारत के प्रत्येक वयस्क नागरिक को मतदान के माध्यम से अपनी सरकार चुनने का अधिकार है या नहीं? यदि कोई भी कार्यवाही उन्हें मताधिकार से वंचित करने का काम कर रही है तो यह बहुत गंभीर बात है। यदि वास्तव में इसके कारण लाखों लोग अपने मताधिकार से वंचित होते हैं तो इसे रोकने की आवश्यकता है।

हम एस आई आर की प्रक्रिया को थोड़ा सिलसिले वार समझने का प्रयास करते हैं। चूंकि प्रत्येक वयस्क को मताधिकार प्राप्त है, सामान्यतया किसी भी राज्य में या क्षेत्र में वयस्क लोगों की संख्या वहां के मतदाता सूचियों में अंकित संख्या के बराबर होनी चाहिए। देश के अनेक राज्यों में मतदाताओं की संख्या, उस राज्य की अनुमानित वयस्क जनसंख्या से अधिक है। उदाहरण के लिए आंध्र प्रदेश में 102%, कर्नाटका में 108%, तेलंगाना में 116%, ओडिशा में 105% और पश्चिम बंगाल में यह 101% है। इनकी तुलना में बिहार में यह 97% है।

इसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार यह होता है कि एक व्यक्ति जिसका नाम एक स्थान पर मतदाता सूची में अंकित है, वह किसी कारणवश दूसरे स्थान पर चला जाता है, तो मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण के समय उसका नाम वहां भी जुड़ जाता है। इस प्रकार उसका नाम दो स्थान पर हो जाता है। व यह यदि पुराने स्थान से नाम कटवाने का प्रार्थना पत्र देता है तो भी उसका नाम नहीं कटता है। मेरा स्वयं का जब 1995 में जयपुर से दूरगुरपुर स्थानांतरण हुआ तो जयपुर में अपना नाम कटवाने के लिए, जिम्मेदार नागरिक की तरह आवेदन किया, किंतु इसकी कोई पुछा सूचना मुझे नहीं मिली। उसके बाद दूरगुरपुर में कलेक्टर के पद का भार ग्रहण करने के बाद मैंने वहां की मतदाता सूची में अपना नाम अंकित करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया और वहां अंकित भी हो गया। यहां मैंने मतदान भी किया। इसके बाद जब मैं जयपुर वापस आया और यहां नाम जुड़वाने का प्रयास किया तो यह जानकर आश्चर्य हुआ कि मेरा नाम तो यहां की मतदाता सूची में से काटा ही नहीं गया था। इस प्रकार लगभग एक वर्ष तक मेरा नाम दो स्थानों पर अंकित रहा। जब यह स्थिति एक आईएसएस अधिकारी के साथ हो सकती है तो पता नहीं कितने अनगिनत व्यक्ति ऐसे होंगे जिनका नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज होगा। नेजस्वी यादव को इसी बात पर तो नोटिस दिया जा रहा है।

अब हम जरा बिहार की ही बात कर लें। 24 जून 2025 को उपलब्ध मतदाता सूची में यह संख्या 7.89 करोड़ थी जबकि अनुमानित वयस्क जनसंख्या बिहार में 8.16 करोड़ थी। जब इस समय राष्ट्रपति का प्रकाशन एक अगस्त 2025 को हुआ है तो अनुमानित वयस्क जनसंख्या 8.18 करोड़ की तुलना में निर्वाचकों की संख्या 7.24 करोड़ है जो कि कुल वयस्क जनसंख्या का 88% है। स्पष्ट है कि बिहार की वयस्क जनसंख्या की तुलना में मतदाताओं की संख्या 94 लाख कम हो गई है।

यह प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में पंविबत है। वहां पर उसकी सुनवाई भी चल रही है। न्यायालय ने कहा है कि एस आर आर की प्रक्रिया, सभी योग्य मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए होनी चाहिए न कि लोगों के नाम काटने के लिए। जिस प्रकार से निर्वाचन आयोग धरातल पर काम कर रहा है, और इसके कई सबूत वीडियो और रिपोर्ट के द्वारा मीडिया में आए हैं, उससे तो यह लगता है कि निर्वाचन आयोग केवल मतदाताओं के नाम काटने के लिए यह काम कर रहा है। 24 जून, 2025 की मतदाता सूचियों में से, ड्राफ्ट मतदाता सूचियों में 65 लाख लोगों के नाम कम हुए हैं। आश्चर्य की बात है कि इसमें एक भी नया नाम नहीं जोड़ा गया। किसी मतदाता का नाम विदेशी नागरिक होने के आधार भी पर नहीं काटा गया है।

निर्वाचन आयोग के अनुसार जिन 65 लाख लोगों के नाम काटे गए हैं उनमें से 22 लाख मृतक हैं, 36 लाख ऐसे हैं जो स्थाई रूप से दूसरे स्थान पर चले गए या जिनकी कोई जानकारी नहीं है एवं 7 लाख ऐसे हैं जिनके नाम एक से अधिक स्थान में अंकित हैं। यह उल्लेखनीय है कि किसी भी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची से हटाने से पूर्व उसकी सुनवाई करना आवश्यक है। ऐसा कुछ भी काम इस बार नहीं किया गया है। निर्वाचन आयोग यह कह रहा है कि जिन लोगों के नाम अंकित नहीं हैं, वे अपनी आपत्ति 31 अगस्त तक दे सकते हैं। यह समझना आवश्यक है कि जिन 7.24 करोड़ लोगों के नाम मतदाता सूची में उपलब्ध हैं, उनमें से भी अनेक ऐसे हैं जो निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित दस्तावेजों में से कोई भी एक देने में समर्थ नहीं हो पाएंगे एवं इसके कारण उनके भी नाम कट जाएंगे। ऐसे व्यक्तियों की संभावित संख्या कुछ भी हो सकती है। एक अनुमान के अनुसार सभी को जोड़कर लगभग डेढ़ करोड़ व्यक्तियों के नाम बिहार की मतदाता सूचियां से काट दिए जाने की संभावना है। ऐसा करना सर्वोच्च न्यायालय के उस आदेश के ठीक विपरीत है जिसके अनुसार लक्ष्म समावेश का होना चाहिए न कि अधिकाधिक निष्कासन का।

जिन लोगों के नाम प्रारूप मतदाता सूची में शामिल हैं, उनमें से भी लाखों लोगों के नाम कटने की संभावना है। एक-एक विधानसभा क्षेत्र में 40 से पचास हजार मतदाताओं के नाम के आगे "not recommended" लिखा है।

प्रश्न यह भी है कि जिन व्यक्तियों के नाम प्रारंभ से मतदाता सूचियों में रहे हैं, वे सभी मताधिकार का उपयोग करते रहे हैं। यदि ये सब अवैध थे तो क्या इनके आधार पर चुनी गई केंद्र और राज्य सरकारें अवैध और असंवैधानिक घोषित की जाएंगी? अब, एस आई आर के नाम पर नागरिकों से अपनी नागरिकता सिद्ध करने के लिए कहना अथवा उसकी आड़ में दस्तावेज मांगना किसी भी रूप में औचित्य पूर्ण नहीं लगता है। वैसे भी जिन दस्तावेजों को निर्वाचन आयोग ने नागरिकता के प्रमाण के रूप में मान्यता दी है, उनसे कैसे नागरिकता सिद्ध होती है, यह चुनाव आयोग द्वारा स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। उदाहरण के लिए यदि किसी के पास भारतीय पासपोर्ट है, उसे भारतीय नागरिक मान लिया जाता है। मजे की बात यह है कि पासपोर्ट बनवाने के लिए नागरिकता का कोई प्रमाण पत्र नहीं मांगा जाता। इसी प्रकार लाखों, करोड़ों लोग जो सरकार के विभिन्न विभागों में नौकरी में थे या हैं उनसे भी नागरिकता का कोई प्रमाण नहीं मांगा गया। सबके द्वारा केवल इस बारे में स्व-घोषणा की गई कि वे भारतीय हैं, और उसी आधार पर उन्हें भारतीय मान लिया गया।

‘आधार’ को भी 11 दस्तावेजों में शामिल नहीं किया गया है जबकि अब लगभग सभी सरकारी कार्यों के लिए ‘आधार’ को अनिवार्य कर दिया गया है। इसका कारण निर्वाचन आयोग द्वारा यह बताया जा रहा है कि कई लोगों ने फर्जी आधार कार्ड बनवा रखे हैं। चुनाव आयोग ने यह किस प्रकार मान लिया कि अब जो 11 दस्तावेज चुनाव आयोग द्वारा चाहे जा रहे हैं, वे उसी तरह फर्जी नहीं बनवाए जा सकते हैं? जिस देश में डिग्रियां तक विश्वविद्यालय द्वारा फर्जी बनाई जा रही हों, वहां जन्म प्रमाण पत्र (स्वयम का या माता-पिता का) फर्जी बनाने में क्या बड़ी बात है? यदि ऐसा हुआ तो निर्वाचन आयोग की सारी प्रक्रिया का अर्थ ही क्या रह जाएगा?

निर्वाचन आयोग यह तर्क दे सकता है कि किसी को आपत्ति होने पर वह प्रमाण सहित अपील, निर्वाचन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है। सामाजिक संगठनों को यह कार्य करने में सबसे बड़ी समस्या यह है कि निर्वाचन आयोग ने जिन व्यक्तियों के नाम काट दिए हैं, उनकी श्रेणी वार सूची सावजनिक नहीं की गई है। अत: उनका भौतिक सत्यापन नहीं किया जा सकता है। पुरानी और नई सूचियों का मिलान करके भी ऐसी जानकारी निकालना लगभग असंभव है, क्योंकि बिहार में बूथों की संख्या 73000 से बढ़ा कर 92000 कर दी गई है।

यदि वास्तव में निर्वाचन आयोग निष्पक्ष है और किसी वर्ग विशेष को मतदान अधिकार से वंचित करने का उद्देश्य नहीं है, तो फिर निर्वाचन आयोग को उन सभी लोगों की सूची जारी करनी चाहिए जिनके नाम जून, 2025 की मतदाता सूची में से हटा दिए गए हैं। ऐसा न करके, निर्वाचन आयोग ने अनावश्यक आशंकाओं को जन्म दिया है।

यदि इसी प्रकार की प्रक्रिया देश के सभी राज्यों में अपनाई जाएगी, जैसा कि निर्वाचन आयोग द्वारा कहा जा रहा है, तो संभावना है कि देश के 100 करोड़ मतदाताओं में से लगभग 10 करोड़ से अधिक मतदाता, मताधिकार से वंचित हो जाएंगे। इसका तो यही अर्थ होगा कि वयस्क होने के बाद भी वे भारत के किसी भी स्थान पर मत देने के योग्य नहीं माने जाएंगे। इतनी बड़ी संख्या किसी भी चुनाव में जीत हार के लिए निर्णायक सिद्ध होगी। सामान्यतया, हार-जीत में अंतर 2-3% का होता है। 10% से अधिक मतदाताओं के नाम कम होने से चुनाव का फैसला पूरी तरह उलट सकता है।

इतनी सारी आशंकाओं को देखते हुए सभी विपक्षी दलों ने संसद में इस पर चर्चा करने के लिए एवं सड़क पर आंदोलन करने की तैयारी कर ली है। इस बारे में चुनाव आयोग ने यदि स्वयं ने निर्णय नहीं लिया एवं सर्वोच्च न्यायालय ने भी एस आई आर की इस प्रक्रिया को नहीं रोका, तो देश में लोकतंत्र के समक्ष एक गंभीर संकट उत्पन्न होने की आशंका हो जाएगी। देश को इस समय निर्वाचन आयोग द्वारा ऐसे मोड़ पर खड़ा कर दिया गया है, जहां एस आई आर पर लड़ाई आर पार की होने वाली है। फिलहाल, सबकी निगाहें सर्वोच्च न्यायालय में 12-13 अगस्त, 2025 को होने वाली सुनवाई पर टिकी है।

–**अतिथि सम्पादक,**
राजेन्द्र भागवानत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)



मदन राठौड़, भाजपा, प्रदेश अध्यक्ष

भारत ने बीते दो दशकों में आतंकवाद के खिलाफ एक लंबी और कठिन लड़ाई लड़ी है, लेकिन फर्क इस बात से पड़ा कि सत्ता में कौन था। 2004 से 2014 तक यूपीए सरकार की नरम, दुलमुल और दुष्टिकरण की नीति ने देश को बार-बार लहलुहान किया। मुंबई का 26/11 हमला जिसमें 166 निर्दोष नागरिक मारे गए, 2005 के दिल्ली धमाकों में 62 लोग मारे गए, 2008 में जयपुर में 63 और अहमदाबाद में 56 लोगों की जान चली गई। ये सिर्फ आंकड़े नहीं, उन मासूमों की कुर्बानी की कहानियाँ हैं जिनका कसूर सिर्फ इतना था कि वे उस वक्त उस जगह पर थे।

और सबसे चिंताजनक बात यह थी कि ऐसी कितनी ही अनगिनत आतंकी घटनाएँ आए दिन देश के किसी न किसी हिस्से को लहलुहान करती रहती थीं, जिनसे हर भारतीय के मन में डर और असुरक्षा का भाव गहराता चला गया। यूपीए के दौर में पूरे देश के नागरिकों के मन में हर वक्त यह डर बैठा रहता था कि न जाने कब और कहां धमाका हो जाए, कितने निर्दोष मर जाएँ।

सबसे शर्मनाक और दुःखद पहलू यह था कि उस समय बाटला हाउस एनकाउंटर में मारे गए आतंकवादियों के लिए तो कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आंसू बहाए, लेकिन क्या उन्होंने कभी दिल्ली, मुंबई, जयपुर या अहमदाबाद की सड़कों पर मारे गए निर्दोष नागरिकों के लिए आंसू बहाए? क्या कभी उन सैकड़ों घरों के जउजने का दर्द महसूस किया? यही यूपीए की नीति का असली चेहरा था – आतंकवादियों के लिए सहानुभूति और आम भारतीयों के जीवन के प्रति बेरुखी, जिसने पूरे देश का मनोबल गिराया और पाकिस्तान जैसे आतंक के प्रायोजक देश का हौसला बढ़ाया।

आज सोचिए, अगर मुंबई, जयपुर और अहमदाबाद के उन भीषण हमलों के बाद उसी वक्त ऑपरेशन सिंदूर जैसी निर्णायक कार्यवाही की गई होती, तो शायद पाकिस्तान को उसी समय सबक

मिल गया होता और आतंकवाद की कमर टूट जाती। लेकिन सत्ता में रही कांग्रेस की नीति हमेशा आतंकवादियों के प्रति नरम रही, पाकिस्तान प्रेम इनके भीतर गहराई तक बैठा रहा, और इसी कारण देश बार-बार लहलुहान हुआ।

2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने के बाद आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति ही बदल दी गई। पहले हमला, फिर जवाब की बजाय घर में घुसकर जवाब देने की नीति आई। उरी हमले के बाद 2016 में सजिकल स्ट्राइक कर पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को तबाह किया गया, पुलवामा हमले के बाद 2019 में बालाकोट एयरस्ट्राइक कर पाकिस्तान की धरती पर जैश-ए-मोहम्मद के अड्डों को नष्ट किया गया, और हाल ही में 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाकर पाकिस्तान और पीओके में लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद और हिजबुल मुजाहिदीन के नौ कैपों को मिट्टी में मिला दिया गया और पाकिस्तान को घुटनों पर ला दिया गया। आज पाकिस्तान अंतरराष्ट्रीय मंचों पर रो रहा है कि हमें मारा गया, लेकिन इधर भारत में कुछ लोग, कांग्रेस के नेता, ऑपरेशन सिंदूर की बारीकियाँ छूछ रहे हैं, हमारे कितने विमान गिरे? कितना नुकसान हुआ?

इस तरह हमारे देश के ऊपर ही सवाल उठा रहे हैं और हमारी सेना का मनोबल गिरा रहे हैं। क्या 1962, 1965 या 1971 की लड़ाइयों में किसी ने ऐसा बेहूदा सवाल पूछा था? सबसे दुःखद बात यह है कि अभी हाल ही में हुए पहलगाम आतंकी हमले में जब भारत ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया, तब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता चिंदंबरम जैसे लोग यह बयान देने लगे कि कैसे पता चला कि आतंकवादी पाकिस्तानी थे? इस तरह के बयान सोधे-सोधे पाकिस्तान के पक्ष को मजबूत करते हैं, क्योंकि पाकिस्तान तो यही दावा कर रहा है कि हमले में मारे गए आतंकी हमारे थे ही नहीं।

और जब भी भारत मजबूती से जवाब देता है, तभी कांग्रेस के नेता राष्ट्रविरोधी बयानों की झड़ी लगाकर देश की आवाज को कमजोर करने की कोशिश करते हैं, सेना के साहस पर प्रश्नचिह्न लगाते हैं और अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारत की स्थिति को कमजोर करने की साजिश रचते हैं। यही कांग्रेस का चाल, चलन और चरित्र हमेशा से रहा है आतंकवादियों के लिए नरम दिल, पाकिस्तान के लिए सहानुभूति और भारत के सुरक्षा बलों पर सवाल। यूपीए के समय गुड मंत्रालय जैसे महत्वपूर्ण पद जिनके हाथ में थे, उनकी नीति कैसी रही होगी, यह उनके हाल के बयानों से

ही साफ दिखता है। मोदी सरकार ने साफ कर दिया है कि अब पाकिस्तान सहन नहीं करेगा, बल्कि हर हमले का जवाब पाकिस्तान की धरती पर जाकर देगा। स्टेट और नॉन-स्टेट एक्टर्स का फर्क खत्म कर दिया गया चाहे हमला कोई संगठन करे, अगर वह पाकिस्तान की शह पर होगा तो उसे पाकिस्तान प्रायोजित हमला माना जाएगा और जवाब भी उसी अंदाज में दिया जाएगा। नतीजा सबके सामने है – 2014 से 2024 के बीच आतंकी घटनाओं में 70 प्रतिशत से ज्यादा कमी आई, नागरिक हताहतों में 80 प्रतिशत तक की गिरावट आई और देश के बड़े शहरों में होने वाले हमलों में भी भारी कमी आई। यही है नया भारत, जो दुश्मन के घर में घुसकर जवाब देता है। कांग्रेस को यह समझना होगा कि सेना पर सवाल उठाना, पाकिस्तान का बचाव करना और आतंकवादियों पर सहानुभूति दिखाना राष्ट्र को कमजोर करता है। हमें गर्व है कि मोदी सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति ने भारत को आत्मविश्वासी, निर्णायक और शक्तिशाली बनाया है और यही नये भारत की सबसे बड़ी ताकत है।

–**मदन राठौड़,**
प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी, राजस्थान

मेड़ता सिटी में मीरा जयंती महोत्सव परवान पर

मेड़ता सिटी, (निसं)। मीरा नगरी मेड़ता सिटी में मीरा जयंती महोत्सव परवान पर है। मीरा जयंती महोत्सव समिति अध्यक्ष जितेंद्र गहलोत, सचिव रवि प्रकाश कमेडिया, कोषाध्यक्ष सुरेंद्र बिड़ला सहित पदाधिकारी व कार्यकर्ता व्यवस्थाओं में जुटे हुए हैं। इस दौरान विभिन्न धार्मिक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं।

मंदिर में मीरा बाई और ठाकुरजी की रजत रेवाड़ी के समक्ष विभिन्न समाज भजन मंडलियों द्वारा लगातार भजन कीर्तन किया जा रहा है। मीरा स्मारक राव दुदागढ़ में भी अनेक कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। इसी क्रम में रविवार रात्रि में श्रीकिशन देव छतरी महंत हरिनायण दाम् पंथी के सानिध्य में मीरा स्मारक में भक्ति संंध्या का आयोजन किया गया, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय गौ ऋषि संत प्रकाशदास महाराज ने भजनों का गायन किया। मीडिया प्रभारी सुनील पुरी ने बताया कि इस दौरान संत प्रकाशदासजी ने गुरु भजनों के साथ भजन संंध्या शुरू की जिसमें



मेड़ता सिटी में मीरा जयंती महोत्सव में संतप्रकाशदास ने भजनों की प्रस्तुति दी।

पालिकाध्यक्ष शोभा लाहोटी, संत धीरजाम पुष्कर रामस्नेही, साखी वीरेंद्र बाई सा आदि मौजूद रहे। इस दौरान संत प्रकाशदासजी ने गुरु भजनों के साथ भजन संंध्या शुरू की जिसमें

मीरा बाई, भगवान शिवजी, कृष्ण-राधा सहित अनेक देवी-देवताओं के भजनों का गायन किया। अनेक भक्ति मय, हास्य, व्यंग्य भजनों के माध्यम उपस्थित जन समुदाय को नाचने को मजबूर कर

दिया। संत प्रकाशदासजी ने अपने उद्बोधन से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की। उन्होंने देश की सेना द्वारा ऑपरेशन सिंदूर द्वारा किए गए वीरतापूर्वक कार्य को आमजन को

■ संत प्रकाशदासजी ने अपने उद्बोधन से गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग की

■ महोत्सव में विभिन्न धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित

अवगत करवाया। देश में नारी शक्ति द्वारा किए वीरता पूर्वक कार्यों को बताया। महोत्सव अध्यक्ष जितेंद्र गहलोत, सचिव सुरेंद्र बिड़ला, वरिष्ठ उपाध्यक्ष लखाराम मेहला, संरक्षक विक्रम शर्मा, हेमंत सामरिया, पुखराज गहलोत, रामेश्वर जोगिड़, विनोद टेलर, भजनदास नगर, दशरत सारस्वत, कैलाश गौड़, शेखर सांखला, रविंद गहलोत, ऋषि भार्ता आदि समिति के पदाधिकारी कार्यकर्ता कार्यक्रमों की व्यवस्थाओं में जुट हुए हैं।

जैसलमेर में गिद्ध पक्षी पर जी.पी.एस. ट्रांसमीटर लगाने का काम हुआ

जैसलमेर, (निसं)। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून ऑफ इंडिया देहरादून के वैज्ञानिक वरुण खेर ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य थार क्षेत्र में पाए जाने वाले शिकारी पक्षियों का परिस्थितिकी तंत्र) पर एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। “रेटर इकोलॉजी इन द थार डेजर्ट” नाम से शुरू हुआ शिकारी पक्षियों पर रिसर्च प्रोजेक्ट जैसलमेर में जारी है और हाल ही में एक इजिप्शियन वल्चर और एक टॉनी ईगल पर ट्रांसमीटर लगाने का काम हुआ है।

वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया देहरादून के वैज्ञानिक वरुण खेर ने बताया कि इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य थार क्षेत्र में पाए जाने वाले शिकारी पक्षियों जैसे बाज, मृत पशुओं को खाने वाले गिद्धों (स्कैवेंजर वल्चर-मृत पक्षी गिद्ध) की पारिस्थितिकी को समझना है। इस रिसर्च के तहत पहली बार थार क्षेत्र में रेटर प्रजातियों पर जीपीएस ट्रांसमीटर आधारित टेलीमेट्री अध्ययन शुरू किया गया है। उन्होंने बताया कि जैसलमेर का डेजर्ट

■ “रेटर इकोलॉजी इन द थार डेजर्ट” नाम से शुरू हुआ शिकारी पक्षियों पर रिसर्च प्रोजेक्ट जैसलमेर में जारी है

■ हाल ही में एक इजिप्शियन वल्चर और एक टॉनी ईगल पर ट्रांसमीटर लगाने का काम हुआ है

नेशनल पार्क रेक्टर पक्षियों के लिए देश का बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है, जहां इनकी संख्या देश के अन्य हिस्सों की तुलना में बहुत अधिक है। यह अध्ययन

इन प्रजातियों की आवाजाही, निवास स्थान, प्रजनन व्यवहार और खतरों को समझने में मदद करेगा। जैसलमेर में स्थित राष्ट्रीय मरु

उद्यान (डेजर्ट नेशनल पार्क) गिद्ध और अन्य शिकारी पक्षियों के लिए काफी खास है। यहां भारत में पाए जाने वाले नौ गिद्धों की प्रजाति में आठ प्रजातियां पाई जाती हैं। इसी पर नजर रखते हुए भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून ने राजस्थान वन विभाग की सहताया से इन शिकारी पक्षियों पर अध्ययन के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। जिसका नाम “रेटर इकोलॉजी इन द थार डेजर्ट” रखा गया है।

गणेश महोत्सव के लिये इको फ्रेंडली प्रतिमाएं बनाई

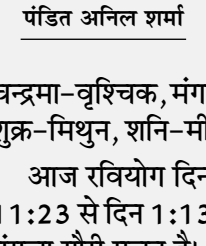
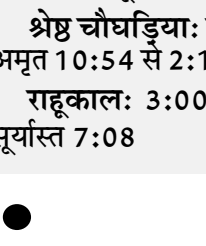
भीलवाड़ा, (निसं)। धर्म एवं समाज सेवा के लिए समर्पित श्रीगणेश उत्सव प्रबंध एवं सेवा समिति भीलवाड़ा के तत्वावधान आगामी 10 दिवसीय गणेश महोत्सव की समरसता 27 अगस्त से शुरू होगी। समिति द्वारा इंदौर के मूर्तिकारों ने भगवान गणपति की आकर्षक मल्टी कलर प्रतिमाएं

स्थानीय स्तर पर तैयार करने का कार्य पूरा कर लिया है। समिति के मीडिया प्रभारी महावीर समदानी के अनुसार गत 30 वर्षों से गणेश महोत्सव मना रही समिति के द्वारा हर वर्ष भगवान गणपति की मूर्ति स्थानीय मांग के अनुसार तैयार की जाती है। इस बार 10 दिवसीय

आयोजन 27 अगस्त गणेश चतुर्थी बुधवार से छह सितंबर शनिवार अनंत चतुर्दशी के दिन विजयन के साथ संपन्न होगा। 1893 में बाल गंगाधर तिलक ने गणेश चतुर्थी को एक सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाने की शुरुआत की जिसका उद्देश्य लोगों को एकजुट करना और ब्रिटिश शासन के खिलाफ राष्ट्रीय

भावना को बढ़ावा देना था। उन्होंने गणेश उत्सव को एक मंच के रूप में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।

भावनाओं को बढ़ावा मिलता है। 10 दिवसीय गणेश महोत्सव के माध्यम से ये भारतीय संस्कृति और परंपराओं को पुनर्जीवित करने का मंच बनता जा रहा है। इस तथ्यैभर को एक ऐसे मंच के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। जहां लोग अपनी संस्कृति और हेरिटेज को मना सके।

राशिकाल मंगलवार 5 अगस्त, 2025	
	सावन मास, शुक्ल पक्ष, एकादशी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2082, ज्येष्ठा नक्षत्र दिन 11:23 तक, ऐन्द्रयन योग प्रातः 7:24 तक, विष्टि करण दिन 1:13 तक, चन्द्रमा आज दिन 11:23 से धनु राशि में संचार करेगा।
	ग्रह स्थिति: सूर्य-कर्क, चन्द्रमा-वृश्चिक, मंगल-कन्या, बुध-कर्क, गुरु-मिथुन, शुक्र-मिथुन, शनि-मीन, राहु-कुम्भ, केतु-सिंह राशि में।
	आज रवियोग दिन 11:23 तक है। कुमार योग दिन 11:23 से दिन 1:13 तक है। आज पवित्र एकादशी व्रत, मंगला गौरी पूजन है।
	श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:15 से 10:54 तक, लाभ-अमृत 10:54 से 2:12 तक, शुभ 3:51 से 5:29 तक। राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 5:57, सूर्यास्त 7:08

मेघ	अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। पारिवारिक परेशानियों के कारण भागदौड़ रहेगी। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित समस्या हो सकती है। दिन के मध्याह्न पश्चात अटके हुए कार्य बनने लगेंगे।
वृष	व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। व्यावसायिक आय में वृद्धि हो सकती है। दिन के मध्याह्न पश्चात अष्टम चन्द्र शुभ नहीं है।
मिथुन	स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी। दिनचर्या में सुधार होगा। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता बनी रहेगी। परिवार में धार्मिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।
कर्क	व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आर्थिक मामलों में संतुलन बनाए रखना ठीक रहेगा।

सिंह	घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।
कन्या	आर्थिक मामलों में परिचितों से सहयोग मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।
तुला	आर्थिक कारणों से अटकें हुए व्यावसायिक कार्य बनने लगेंगे। संभावित खोत से धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों से संबंधित बातें सफल रहेंगी।
वृश्चिक	व्यावसायिक कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटकें हुए कार्य बनने लगेंगे। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा।

धनु	घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। पारिवारिक कार्यों के कारण भागदौड़ रहेगी। मन में असंतोष बना रहेगा। दिन के मध्याह्न पश्चात मानसिक तनाव से राहत मिल सकती है।
मकर	आर्थिक/वित्तीय मामलों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक विवादों से राहत मिल सकती है।
कुंभ	व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। अटकें हुए कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।
मीन	नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होगा। अटकें हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। परिवार में शुभ-मार्गालिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

लालसोट में ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना का सीएम भजनलाल ने किया शिलान्यास

हर गांव-ढाणी तक सुविधाएं पहुंचाकर लोगों का जीवन बेहतर बनाना हमारा संकल्प : भजनलाल

दौसा/जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के हर गांव, हर ढाणी और हर व्यक्ति तक सुविधाएं पहुंचाकर लोगों का जीवन बेहतर बनाना हमारा संकल्प है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को सशक्त एवं समृद्ध बनाने का लक्ष्य लेकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सोमवार को दौसा जिले के लालसोट विधानसभा क्षेत्र स्थित डूंगरपुर गांव में आयोजित समारोह में रिमोट का बटन दबाकर ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए कहा कि महादेव की कृपा से प्रदेश में भरपूर बारिश से जलाशय लबालब हो गए हैं और ईसरदा बांध में भी खूब पानी आया है। उन्होंने कहा कि ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना के तहत लालसोट में लगभग 350 करोड़ रुपये की लागत से 8 स्वच्छ जलाशयों, 5 पंप हाउस, 47 उच्च जलाशयों का निर्माण किया जाएगा। इसमें 280 किलोमीटर राईजिंग मुख्य पाइप लाइन, 200 किलोमीटर से अधिक मुख्य पाइप लाइन एवं 1360 किलोमीटर वीडोएस पाइप लाइन बिछाई जाएगी।



सीएम भजनलाल शर्मा ने बटन दबाकर ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना का शिलान्यास किया।

उन्होंने कहा कि वर्ष 2027 तक पूर्ण किए जाने वाले इन कार्यों से 302 गांवों की लगभग 5 लाख 58 हजार आबादी और लालसोट की करीब 69 हजार आबादी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा। शर्मा ने कहा कि लालसोट विधानसभा में 120 करोड़ रुपये से अधिक के अन्य विकास कार्यों की भी स्वीकृति दी गई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि लालसोट

विधानसभा के लिए 116 करोड़ रुपए का प्रावधान कर संबंधित कार्यों को तेजी से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एसएच-24 से एनएच-11 एई वाया नांगल मोड़, देवली रोड-लालसोट बाईपास के नवीनीकरण एवं चौड़ाईकरण हेतु कार्यदिश जारी किए जा चुके हैं। एनएच 148 डूंगरपुर मोड़ से डोब बाया हरिपुरा एवं लालसोट से खटवा तक सड़क नवीनीकरण एवं

चौड़ाईकरण कार्य करवाया जा रहा है। लालसोट नगर पालिका को नगर परिषद् में क्रमोन्नत किया गया है। साथ ही श्यामपुरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में एवं कन्या महाविद्यालय, लालसोट को पीजी में क्रमोन्नत किया गया है।

समारोह में कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री डॉ. किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा

■ ‘ईसरदा-दौसा पेयजल परियोजना से लगभग 6.27 लाख लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सकेगा’

के नेतृत्व में राज्य की डबल इंजन सरकार किसानों का जीवन स्तर बेहतर बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उनकी पैदावार बढ़ाने के लिए उच्च किस्म के खाद-बीज और कीटनाशक उपलब्ध कराए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अतिवृष्टि प्रभावित लोगों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। कृषि मंत्री ने दौसा क्षेत्र में ईसरदा बांध का पानी उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल ने कहा कि गत सरकार के कार्यकाल में जल जीवन मिशन में व्यापक भ्रष्टाचार हुआ जिससे इसके कार्य समय पर पूरे नहीं हुए। अब हमारी सरकार द्वारा जल जीवन मिशन के अंतर्गत गुणवत्तापूर्ण कार्य तेजी से पूरे किए जा रहे हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सिंदूर का पौधा भी लगाया।

2.16 करोड़ का डोडा-पोस्त जब्त, आरोपी गिरफ्तार

नागौर, (निसं)। नागौर पुलिस ने जिला स्तरीय अभियान ऑपरेशन नीलकंठ के तहत एक खेत में दबिश देकर 1441 किलोग्राम अवैध डोडा-पोस्त जप्त किया है। अंतर्देशीय बाजार में बरामद डोडा पोस्त की अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ 16 लाख रुपए है। सयुक्त कार्रवाई में पांचौड़ी थाना, सदर और नागौर डीएसटी टीम शामिल रही।

नागौर एसपी मधुल कच्छवा ने बताया कि नशे व मादक पदार्थों के खिलाफ नागौर जिला स्तर पर ऑपरेशन

नीलकंठ चलाया जा रहा है। सूचना मिली कि भेड़ गांव का श्रवणराम बिश्नोई (40) खेत में अवैध डोडा-पोस्त छिपा रहा है। सूचना की पुष्टि होते ही स्थानीय पांचौड़ी थाना टीम को अवगत कराया गया। टीम ने आरोपी श्रवणराम के खेत पर छापा मारा। पुलिस ने वहां से 50 कट्टों में भरा 1441 किलो डोडा-पोस्त बरामद किया और मौके से ही आरोपी श्रवण राम बिश्नोई को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब इस तस्करी नेटवर्क से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश में जुट गई है।

सातवीं मंजिल से नीचे गिरा बालक, मौत

कोटा, (निसं)। बोरखेड़ा थाना इलाके में खेलते समय पैर फिसलने से सातवीं मंजिल की सीढ़ियों से नीचे गिरने से बालक की मौत हो गई। 12 वर्षीय बालक हर्ष प्रधान अपार्टमेंट की छत पर खेलते समय पैर फिसलने से सीढ़ियों पर आ गया और सीधे नीचे फ्लोर पर गिर गया। जिसे अस्पताल लाया गया। जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। बोरखेड़ा थानाधिकारी

देवेश भारद्वाज ने बताया कि मृतक बालक हर्ष प्रयाग उड़ीसा का निवासी है जो परिवार वालों के साथ कोटा में कुछ ही महीने पहले आया था। थानाधिकारी ने बताया कि मृतक बालक हर्ष की मां इलाके के कोरल पार्क स्थित श्याम अपार्टमेंट में वाईन का काम करती है। बालक अपार्टमेंट की छत पर खेल रहा था, पैर फिसलन से बालक सीढ़ियों से गिरता हुआ नीचे आ गया।

पावटा, (निसं)। तेज रफ्तार डंपर ने एक महिला को कुचला दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया और सड़क मार्ग जाम कर दिया।

■ आक्रोशित परिजनों व ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया

■ मुवावजा देने के आश्वासन के बाद चार घंटे बाद धरना समाप्त हुआ

प्रागपुरा थाना क्षेत्र के बुचारा निवासी लक्ष्मी देवी (48) पत्नी प्रहलाद सोमवार की सुबह घर से अपने भाई के लड़के अजय के साथ बाइक पर पावटा डॉक्टर को दिखाकर दवाई लेकर वापस बुचारा आ रही थीं। उसी समय समय ग्राम बुचारा पहुंचने पर कालीबाय के पास क्रशर के डंपर ने



हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई।

महिला को रौंद दिया, जिससे मौके पर ही महिला की मौत हो गई। सुबह करीब 12 बजे हुई इस दुर्घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया।

आसपास के ग्रामीण और परिजन दौड़कर मौके पर पहुंच गए। घटना की जानकारी लगते ही डंपर चालक तो मौके से भाग गया। आसपास के लोगों से सूचना गांव पहुंची, तो देखते ही

देखते लोगों की भीड़ मौके पर पहुंच गई और जाम जैसी स्थिति निर्मित हो गई। महिला के मौत की खबर सुनते ही परिजन व ग्रामीण आक्रोशित हो गए और मार्ग को जाम कर मृत महिला के शव को लेकर धरने पर बैठ गए व क्रेशर व डंपर मालिक को मौके पर बुलाने व क्षेत्र में इन वाहनों की वजह से घंटित हो रही दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने

राज्य सरकार ने 103 शिक्षा अधिकारियों के तबादले किये

बीकानेर, (निसं)। राज्य सरकार ने 24 घंटे में 612 शिक्षा अधिकारियों के ट्रांसफर कर दिया। इनमें प्रिंसिपल के साथ ही विलेज लेवल से स्टेट के अधिकारी भी शामिल हैं। पहली लिस्ट रविवार को 509 प्रिंसिपल की जारी हुई थी। इसके बाद सोमवार सुबह पहले 35 और फिर 68 शिक्षा अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। जून 2023 के बाद से शिक्षा विभाग में ट्रांसफर नहीं हुए थे। इनमें कई ऐसे भी थे, जो कांग्रेस सरकार में लगे हुए थे। इधर, इससे पहले शिक्षा विभाग की ओर से ट्रांसफर से रोक हटाने

और 10 हजार टीचर के ट्रांसफर का प्रस्ताव बनाकर भेजा था। हालांकि सरकार ने इसे खारिज कर पूरा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया है।

प्रिंसिपल ट्रांसफर की एक और लिस्ट सोमवार सुबह जारी की गई। इस लिस्ट पर माध्यमिक शिक्षा निदेशक के ई-साइन देर रात तीन बजे हुए हैं। ये लिस्ट सोमवार अल सुबह सार्वजनिक हुई। इसमें 35 प्रिंसिपल को पोस्टिंग दी गई है। इसमें 23 प्रिंसिपल वे हैं, जिन्हें अलग-अलग कारणों से एपीओ किया गया था। वहीं चार प्रिंसिपल का ट्रांसफर

संशोधित किया गया है। इन्हें स्कूल से स्कूल में ही लगाया गया है। इसमें बीकानेर के महारानी स्कूल की प्रिंसिपल शारदा पहाड़िया भी शामिल हैं। जिन्हें पहले देशनोक लगाया गया था, लेकिन अब बीकानेर शहर में ही उसकी की बारी स्कूल में प्रिंसिपल लगाया गया है। इसके बाद तीसरी लिस्ट सुबह साढ़े छह बजे जारी हुई है। इसमें बीकानेर और अजमेर के राजकीय उच्च अध्ययन शिक्षण संस्थान (टीटी कॉलेज) में जिला शिक्षा अधिकारी, प्रिंसिपल और लेक्चरर लगाए गए हैं।

बिजली का पोल गिरने से बुजुर्ग की मौत

टोंक, (निसं)। कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ा कुआं, पोली हवेली के पास रविवार को पेड़ काटते समय पेड़ बिजली के तारों पर गिरने से बिजली पोल टूट कर नीचे किराना दुकान पर खड़े बुजुर्ग के सिर पर गिर गया, जिससे बुजुर्ग का सिर फटने से उसकी मौत हो गई।

थाना कोतवाली प्रभारी भंवरलाल वैष्णव ने बताया कि पोली हवेली निवासी अवरार अहमद (72) जो किराने की दुकान पर घरेलू सामान लेने गया था, तभी दुकान के पास काटा जा पेड़ बिजली की लाइन के तार जर्जर

पड़े बिजली के पोल आ गिरा तभी पोल टूटकर अवरार अहमद के सिर पर गिर पड़ा, जिससे उसका सिर फट गया। जिसे परिजनों और मोहल्लेबासियों ने अस्पताल पहुंचाया, लेकिन जयपुर ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। वहीं मृतक के परिजनों ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कराकर घटना में बिजली निगम की लापरवाही का आरोप लगाया है, जहां परिजनों ने मुआवजा देने और लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है।

पर लिखकर परिवारी को बताया, परन्तु परिवारी ने सभापति से कहा कि मैं 30 हजार रुपये ही दूंगा। इस पर सभापति ने आकाश कनिष्ठ सहायक से मिलने के लिये कहा। परिवारी आरोपी आकाश कलोसिया से मिला तो उसने कहा कि मेरे पास सभापति का कॉल आया था, उन्होंने 40 हजार रुपये की कहा है, मैं सभापति संजय शुक्ला से पूछकर ऊनके बताया अनुसार व्यक्ति को रुपये दिलाऊंगा। रिश्तत की मांग का सत्यापन होने के पश्चात एसबी झालावाड़ द्वारा सोमवार को ट्रेप कार्यवाही कर संजय शुक्ला सभापति नगर परिषद झालावाड़ के बताया अनुसार आकाश कलोसिया कनिष्ठ सहायक ने अजय कुमार मारवाड़ा टैन्ट हाउस को 30 टीमा हजार रुपये रिश्तत राशि दिलावाई, जिस पर अजय कुमार प्राइवेट व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी के घर की तलाशी जारी है। एसबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जायेगा।

■ मामले में आरोपी परिषद सभापति संजय शुक्ला फरार, एसबी टीम तलाश में लगी हुई है

■ पट्टा जारी करने की फाइल पर हस्ताक्षर करने के लिये 50 हजार रुपये की मांग की

पर लिखकर परिवारी को बताया, परन्तु परिवारी ने सभापति से कहा कि मैं 30 हजार रुपये ही दूंगा। इस पर सभापति ने आकाश कनिष्ठ सहायक से मिलने के लिये कहा। परिवारी आरोपी आकाश कलोसिया से मिला तो उसने कहा कि मेरे पास सभापति का कॉल आया था, उन्होंने 40 हजार रुपये की कहा है, मैं सभापति संजय शुक्ला से पूछकर ऊनके बताया अनुसार व्यक्ति को रुपये दिलाऊंगा। रिश्तत की मांग का सत्यापन होने के पश्चात एसबी झालावाड़ द्वारा सोमवार को ट्रेप कार्यवाही कर संजय शुक्ला सभापति नगर परिषद झालावाड़ के बताया अनुसार आकाश कलोसिया कनिष्ठ सहायक ने अजय कुमार मारवाड़ा टैन्ट हाउस को 30 टीमा हजार रुपये रिश्तत राशि दिलावाई, जिस पर अजय कुमार प्राइवेट व्यक्ति को रंगे हाथों पकड़ा गया। आरोपी के घर की तलाशी जारी है। एसबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान किया जायेगा।

रिश्तत लेते हेड कांस्टेबल गिरफ्तार

उदयपुर, (निसं)। पति की मदद के लिए परिवारिया के सहयोगी से एक हजार रुपये रिश्तत लेते गोवर्धन विलास पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल को भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो टीम ने गिरफ्तार किया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर टीम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनन्त कुमार ने बताया कि 4 अगस्त को परिवारिया लक्ष्मीबाई निवासी काया ने सहपरिवारी भगवान निवासी काया के साथ ब्यूरो कार्यालय उदयपुर में एक

■ थाने में मारपीट नहीं करने एवं जमानत में मदद करने के एवज में दो हजार रुपये रिश्तत मांगी

रिपोर्ट दी। उसने बताया कि गोवर्धन विलास पुलिस थाने के हेड कांस्टेबल संजय कुमार मीणा जो एक्सआईएक्ट मामले में बंदी मेरे पति होमा के साथ थाने में मारपीट नहीं करने एवं जमानत में मदद करने के एवज में 2 हजार रुपये रिश्तत की मांग कर रहा है। जिसका सत्यापन कराया तो हेडकांस्टेबल संजय कुमार ने 1500 रुपये की रिश्तत उसी समय ले ली। शेष नकदी कोर्ट में परिवारजन से उपलब्ध करवाने के लिए कहा। सत्यापन होने पर एसबी के पुलिस निरीक्षण नरपतिसिंह मय टीम ने संजय मीणा को कोर्ट परिसर में परिवारी से 1000 हजार रुपये रिश्तत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो की टीम आरोपी के मकान की तलाश कर रही है।

बीस हजार की रिश्तत लेते हेड कांस्टेबल गिरफ्तार

उदयपुर, (निसं)। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इन्टेलिजेंस उदयपुर की टीम ने लूट के मामले में आरोपी नहीं बनाने तथा जब्त कार छोड़ने के एवज में पुलिस के हेडकांस्टेबल को बीस हजार रुपये रिश्तत लेते गिरफ्तार किया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार एक अगस्त को पीड़ित यशपालसिंह चौहान निवासी कल्ला, खेड़ी विरान पोस्ट गुंजोल नाथद्वारा राजसमंद ने भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इंटेलीजेंस यूनिट उदयपुर को रिपोर्ट दी। जिसमें उसने बताया कि मुझे खमनोर पुलिस थाने में दर्ज प्रकरण में लूट के मामले में आरोपी नहीं बनाने एवं जब्तशुदा कार को छोड़ने के एवज में थानाधिकारी खमनोर शैतानसिंह नाथावत के रीडर कृष्णकुमार पुत्र सरदाराराम निवासी मोटूका तहसील नीमकाथाना थाना सीकर हॉल हेडकांस्टेबल पुलिस थाना खमनोर 26 हजार रूपये रिश्तत की मांग कर रहा है। पूर्व में मुझसे डरा धमकाकर 35 हजार रूपये वसूल कर चुका है।

जिस पर एक अगस्त को शिकायत

■ लूट के मामले में आरोपी नहीं बनाने तथा जब्त कार छोड़ने के एवज में रिश्तत ली

का सत्यापन किया तो रीडर हेडकांस्टेबल द्वारा थानेदार के नाम से रिश्तत मांगने की पुष्टि की गई। इस पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो उदयपुर रेंज के उप महानिरीक्षक पुलिस प्रहलादसिंह कृष्णाय के सुपरिवजन में ब्यूरो टीम की प्रभारी निरीक्षक डॉ. सोनु शेखावत के नेतृत्व में एएसआई मुनीर मोहम्मद, सहायक प्रशासनिक अधिकारी दलपतसिंह, कांस्टेबलन अजय कुमार, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इंटेलीजेंस यूनिट कनिष्ठ सहायक लक्ष्मणसिंह टीम ने सोमवार को थानाधिकारी के नाम पर हेड कांस्टेबल कृष्णा कुमार को 20 हजार रूपये रिश्तत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो की टीम मामले में खमनोर थानाधिकारी की संदर्भ भूमिका के मामले में जांच कर रही है।

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
ई-निविदा 04/2025-26
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर द्वारा कृषि महाविद्यालय, सुमेरपुर तथा कृषि अनुसंधान उपकेंद्र, सुमेरपुर में श्रमिकों की आपूर्ति करने हेतु ऑनलाईन ई-निविदा आमंत्रित की जाती है। निविदा संबंधी विस्तृत विवरण एवं जानकारी www.sppp.raajasthan.gov.in एवं eproc.raajasthan.gov.in पर उपलब्ध है। UBN No. : JAU2526SLRC00071
Eproc ID: 2025_AGUJD_492103_1
लघु.समा.र/सी/25/1470

Government of Rajasthan
Water Resources Department
Office of the Executive Engineer
Water Resources Division Dholpur
Tel & Fax No. 05642-228880 E-mail- eeWRDDholpur1@gmail.com
E-NIT NO. 06 YEAR 2025-26

No. 1597 Date-25.07.2025
On behalf of government of Rajasthan NIT No. 06 Year 2025-26 is invited from eligible contractor for 04 Nos. works cost of works is Rs. 66.41 Lacs. The detail of works is available on following websites.
UBN No. (1) WRD2526GLOB00768, (2) WRD2526GLOB00769, (3) WRD2526GLOB00770, (4) WRD2526GLOB00771
1. www.dinraajasthan.gov.in 2. www.sppp.raajasthan.gov.in

OFFICE OF THE EXECUTIVE ENGINEER
WATER RESOURCES DIVISION, JHALAWAR
NO. E.E./WRJHA/JNIT-05/2025-26/1426-54 Date- 25.07.2025
E-NIT NO. 05/2025-26
On Behalf of The Governor of Rajasthan, e-tender is invited from interested bidders for the work for 1. Plantation work (ERCP) Mission Haryana Rajasthan water resources Division Jhalawar Tehsil Jhalapatan, Bakani, Pachphar. (Est. Cost Rs. 39.25 Lac) 2. Plantation work (ERCP) Mission Haryana Rajasthan water resources Division Jhalawar Tehsil Khanpur. (Est. Cost Rs. 39.25 Lac) for Completion period of 03 Months (Including Rainy Season) from 26.07.2025 (9.30 AM) to 06.08.2025 (06.00 PM). Other particulars, terms & conditions may be seen on the procurement portal www.eproc.raajasthan.gov.in, www.diprc.raajasthan.gov.in, sppp.raajasthan.gov.in or www.watersources.raajasthan.gov.in
NIB CODE- WRD2526A0302, UBN For Item No. 01-WRD2526WSOB00796, UBN For Item No. 02-WRD2526WSOB00797

(Pankaj Singh)
Executive Engineer
Water Resources Division, Jhalawar
DIPRC/10883/2025

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर
विज्ञप्ति
दिनांक-28.07.2025
आयोग के वि. सं. 09/2024-25 दिनांक 05.08.2024 द्वारा आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग के लिए सहायक सांख्यिकी अधिकारी (ASSISTANT STATISTICAL OFFICER) के कुल 43 (एक अनुसूचित क्षेत्र-31 एवं अनुसूचित क्षेत्र-12) पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाईन आवेदन पर आमंत्रित किये गये थे। विभागा द्वारा गैर अनुसूचित क्षेत्र के पदों की संख्या में 50 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि किये जाने के फलस्वरूप उक्त पदों हेतु दिनांक 30.07.2025 से दिनांक 13.08.2025 को रात्रि 12.00 बजे तक ऑनलाईन आवेदन पर पुनः आमंत्रित किये जाते हैं। इसके पश्चात रिक निम्निय हो जाएगा। ऑनलाईन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को आयोग के ऑनलाईन पोर्टल <https://rpsc.raajasthan.gov.in> पर उपलब्ध Apply online link को Click कर अथवा एस.एस.ओ. (SSO) पोर्टल <https://sso.raajasthan.gov.in> से Login कर Citizen Apps (G2C) में उपलब्ध Recruitment Portal का चयन कर One Time Registration (OTR) करना होगा। विभाग से प्राप्त संशोधित वकीवार वकीकरण एवं अन्य सूचना के संबंध में आयोग की वेब-साइट पर जारी शुद्धि पत्र संख्या 6/2025-26 का अभ्यर्थी अवलोकन कर सकते हैं।
DIPRC/10916/2025 (रामनिवास मेहता) सचिव

पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई के लिए आम सूचना

विषय:- मैसर्स गीतांजलि स्टील प्राइवेट लिमिटेड, निकट ग्राम गढ़ तकनेट, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में प्रस्तावित धातुकर्म उद्योग (लौह और अलौह), खनिज लाभकारीकरण, ताप विद्युत संयंत्र परियोजना हेतु पर्यावरण स्वीकृति के लिए लोक सुनवाई।

- सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक मैसर्स गीतांजलि स्टील प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रस्तावित धातुकर्म उद्योग (लौह और अलौह), खनिज लाभकारीकरण, ताप विद्युत संयंत्र परियोजना जोकि, निकट ग्राम गढ़ तकनेट, तहमील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर में स्थित है से संबंधित प्रार्थना पत्र मय दस्तावेज पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक लोक सुनवाई हेतु प्रस्ताव राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल (यहाँ तथा बाद में मण्डल के नाम से अभिलिखित) को प्रस्तुत किया गया है।
- और चूंकि मैसर्स गीतांजलि स्टील प्राइवेट लिमिटेड, ने राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल को उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से पूर्व आवश्यक परियोजना की लोक सुनवाई हेतु मण्डल को आवेदन प्रस्तुत किया है। उक्त परियोजना हेतु वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना संख्या एस. ओ. 1533 दिनांक 14.09.2006 और एस.ओ. 141 ई दिनांक 15.01.2016 के प्रावधानों के अनुसरण में जन सुनवाई हेतु इस आशय की सूचना जारी कर 30 दिवस का नोटिस दिया जाना आवश्यक है।
- उक्त परियोजना से सम्बंधित मंक्षिप्त अभिलेख (कार्यकारी मारांश) एवं संस्तिप काव्यपालक मार अभिलेख निम्न कार्यालयों में अवलोकनार्थ उपलब्ध है:-
 - जिला कलक्टर, सीकर।
 - अतिरिक्त जिला कलेक्टर, नीमकाथाना, जिला सीकर।
 - राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मुख्यालय 4, संस्थानिक क्षेत्र झालाना डूंगरी, जयपुर।
 - क्षेत्रीय कार्यालय, वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, ए-218, अरण्यभवन झालाना संस्थानिक क्षेत्र जयपुर।
 - महा प्रबन्धक, जिला उद्योग केंद्र, सीकर।
 - उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
 - क्षेत्रीय प्रबंधक रीको, सीकर।
 - ग्राम पंचायत, गढ़ तकनेट, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
 - राजीव गाँधी मेसेवा केंद्र, ग्राम गढ़ तकनेट, तहसील श्रीमाधोपुर, जिला सीकर।
 - निदेशक, पर्यावरण विभाग, कमरा संख्या 8240 द्वितीय तल, 3-प (एमएमओ) भवन, सचिवालय, जयपुर।
 - क्षेत्रीय अधिकारी, राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल मीकर जिला सीकर।

अतः सर्वसाधारण को कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, सीकर के पत्र क्रमांक 2461 दिनांक 25.07.2025 के क्रम में इस आम सूचना के माध्यम से एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति से संबंधित जन सुनवाई हेतु दिनांक 10.09.2025 (बुधवार) को प्रातः 11:30 बजे, स्थान-राजीव गांधी सेवा केन्द्र, ग्राम गढ़ तकनेट, तहसील श्रीमाधोपुर एवं जिला सीकर में उपस्थित होकर अपने लिखित / मौखिक आक्षेप / सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं।

साथ ही इस सम्बन्ध में लिखित सुझाव/आपत्ति इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस के अन्दर क्षेत्रीय कार्यालय राजस्थान राज्य प्रदूषण मण्डल, सीकर जिला सीकर में दिये जा सकते हैं। यह आम सूचना वैश्विक महामारी कोविड-19 से सम्बंधित केंद्रीय/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर पारित निर्देशों के अनुरूप एवं अधीन रहेगी तथा सभी प्रावधानों/सावधानियों की पालना सुनिश्चित करनी होगी।

क्षेत्रीय अधिकारी
राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल, सीकर

“ विकसित राजस्थान-खुशहाल राजस्थान” बनाने में जुटी है भजनलाल सरकार : पूनिया

सतीश पूनियां ने नागौर के रोल में राज. विद्यालय परिसर में बैठियों के साथ पौधारोपण किया

जयपुर/नागौर। मारवाड़, मेवाड़-वागड़ के सात जिलों के चार दिवसीय प्रवास पर भाजपा हरियाणा संगठन प्रभारी, भाजपा राजस्थान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां सोमवार को डीडवाना-कुचामन और नागौर के प्रवास पर रहे, जहां पूनियां ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अभिनव पहल एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान के तहत कुचामन-डीडवाना में कार्यकर्ताओं एवं जनप्रतिनिधियों के साथ पौधारोपण किया और नागौर जिले के रोल में राजकीय विद्यालय परिसर में बैठियों के साथ एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत पौधारोपण किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान जिले के विकास कार्यों को लेकर चर्चा कर फीडबैक भी लिया।

पूनियां ने नागौर के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमाकांत शर्मा के निवास पर पहुंचकर उनकी माताजी दुर्गा देवी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त कर परिवारजनों को ईश्वर से संबल प्रदान करने की प्रार्थना की और डॉडस बंधाया। मीडिया से बातचीत में सतीश पूनियां ने कहा कि 2018 से 2023 तक कांग्रेस की अशोक गहलोत सरकार रही। इन पांच सालों



भाजपा राजस्थान पूर्व प्रदेशाध्यक्ष डॉ. सतीश पूनियां का कार्यकर्ताओं ने नागौर में स्वागत किया।

में तत्कालीन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अधिकांश समय तो कुर्सी बचाने में लगे रहे। कांग्रेस पार्टी के भीतर इतना विरोध था कि उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट को बर्खास्त करना पड़ा। उन 5 सालों में जो अराजकता एवं विगड़ी कानून व्यवस्था का दंश प्रदेश ने झेला, वो विरासत भाजपा की भजनलाल शर्मा सरकार को मिली है, जो विकसित राजस्थान और खुशहाल

राजस्थान बनाने में जुटी है।

पूनियां ने ब्यूरोक्रेसी के बढ़ते हस्तक्षेप को लेकर मीडिया द्वारा पूछे गये सवाल के जवाब में कहा कि ब्यूरोक्रेसी सरकार की योजनाओं के अनुसार ही कार्य कर रही है। राज्य में पंचायतीराज और स्थानीय निकाय संस्थाओं को पुनर्जीवित करना, उनको आर्थिक एवं प्रशासनिक रूप से खड़ा किया जा रहा है, जो राज्य हित में अच्छा कदम है। उन्होंने कहा कि, राज्य में पुनर्संामांकन

का काम लगभग पूरा हो चुका है, कांग्रेस शासन में जो गड़बड़ी हुई थी, उसे दुरुस्त करने में कुछ समय लगा, भाजपा सरकार में यह चुनाव व्यवस्थित तरीके से निर्धारित समय में होगा। उन्होंने कहा कि विपक्ष में रहते हुये 2019-2023 के बीच ऐसा पहली बार हुआ कि भाजपा ने 21 जिला परिषदों पर कब्जा किया था, पंचायत समिति और जिला परिषद के अधिकार सदस्य भाजपा के जीते थे, आजादी के बाद पहली बार राज्य में

- डॉ. सतीश पूनियां ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात के दौरान जिले के विकास कार्यों को लेकर चर्चा कर फीडबैक भी लिया**

- पूनियां ने नागौर के पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष रमाकांत शर्मा के निवास पर पहुंचकर उनकी माताजी दुर्गा देवी के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की**

विपक्ष में रहते हुए भाजपा की पंचायतीराज चुनाव में सबसे बड़ी जीत थी, इस दौरान सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी को पंचायतीराज चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा और अब विकसित राजस्थान बनाने के लिए संकल्पित होकर काम कर रही भाजपा सरकार के शासन में निकाय से लेकर पंचायतीराज चुनाव में भी भाजपा बड़ी जीत हासिल करेगी, ऐसा लोगों ने मन बना लिया है।

आकांक्षा हाट मेले का आयोजन

नागौर/जायल, (निसं)। स्थानीय उत्पादों और कारीगरों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से वोल्क फॉर लोकल अभियान के अंतर्गत सोमवार को जायल में आकांक्षा हाट मेले का शुभारंभ महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री डॉ. मंजू बाघमार व जिला कलेक्टर अरुण कुमार पुरोहित ने फीता काटकर किया।

इस अवसर पर जिला कलेक्टर पुरोहित ने आकांक्षा हाट मेले की जानकारी दी तथा स्थानीय कारीगरों और स्वयं सहायता समूहों के उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए सभी से अधिकतम सहयोग करने का आह्वान किया। उन्होंने बताया कि मेले का आयोजन 9 अगस्त तक किया जाएगा।

भरतपुर कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में छत का प्लास्टर गिरा

भरतपुर, (निसं)। भरतपुर जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय परिसर में छत का प्लास्टर गिरने से हड़कंभ मच गया। नीचे बैठे एडवोकेट एवं अन्य लोग बाल-बाल बच गए। एडीएम सिटी ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का मौका मुआयना किया। भवन की जांच के लिए मौके पर पीडब्ल्यूडी के अधिकारी बुलाकर निरीक्षण कराया जा रहा है।

जिला कलेक्ट्रेट परिसर के भवनों की छत क्षतिग्रस्त है और आगे भी ऐसा हादसा देखने को मिल सकता है। एडवोकेट बुजेंद्र बिहारी शर्मा ने बताया कि जिला कलेक्ट्रेट परिसर स्थित आर आर वन कोर्ट के सामने मेरा चैबर है। मैं और क्लाइंट बैठे हुए थे। ऊपर से छत से प्लास्टर का टुकड़ा हमारे ऊपर आकर गिरा हम और क्लाइंट बाल-बाल बच गये। उन्होंने कहा कि हमने पूर्व में उच्च अधिकारियों को जर्जर भवन के बारे में अवगत करा चुके हैं

सड़क टूटकर नदी में बही, बाँली व बामनवास पाकिस्तान की ओर से एक बार फिर हेरोइन तस्करी का प्रयास

बाँली-बामनवास, (निसं)। क्षेत्र के बरनाला तहसील अंतर्गत टिगरिया-निमोद सड़क मार्ग के मध्य स्थित मौरेल नदी की सड़क पर बनी पुलिया के दोनों किनारों से सड़क टूटकर नदी में बह जाने के कारण बाँली एवं बामनवास उपखंड के करीब 40 गांव का आवागमन बाधित हो गया।

ग्रामीणों ने बताया कि सोमवार को सुबह जब पुलिया व सड़क मार्ग टूटा, तब एक बाइक सवार बह गया, जिसे ग्रामीणों ने नदी में कूदकर बड़ी मुश्किल से बचाया। ग्रामीणों ने बताया कि गत दिनों हुई अत्यधिक वर्षा के कारण नदी उफान पर है एवं पुलिया सड़क मार्ग पर करीब तीन फीट पानी बह रहा था। इस कारण गत 5 दिन से यातायात बाधित था। अभी जलस्तर थोड़ा कम पड़ा था तो पुलिया के आसपास पूरी सड़क नदी में समा गई।

इस कारण बाँली एवं बामनवास उपखंड मुख्यालय के करीब 40 गांवों का संपर्क टूट गया, जिसमें बाँली उपखंड के निमोद, करेल, बरियारा,



मौरेल नदी पर बनी पुलिया के दोनों किनारों से सड़क टूटकर नदी में बह गई।

टोंड, जस्टाना, पीपलदा, कोडियाई, गालद, कीरतपुरा, मलारना चौड़ सहित कई गांवों का संपर्क कटा हुआ है। इसी प्रकार बामनवास उपखंड के बरनाला, बाटीदा, बेरखंडी, भावड़, जीवद, सुंदरी, मीना ठीकरी,

रामसिंहपुरा, टिगरिया, बिछोछ, भंवरकी, साचोली, चांदनहोली, पिपलई, बाढ़ व मोहनपुरा का संपर्क कटा हुआ है। इस समस्या के कारण स्थानीय लोगों को करीब 25 किलोमीटर का अतिरिक्त चक्कर

काटकर भाड़ौती मेगा हाइवे या लालसोद, बगड़ी होकर अपने गंतव्य तक पहुंचाना पड़ रहा है। स्थानीय निवासियों का टूटी सड़क से पैदल निकलना भी दुश्वार हो रहा है, चार दिन अवकाश के बाद

72.50 लाख की हेरोइन जब्त, दो जने गिरफ्तार

- एक आरोपी नरेंद्र सिंह कुछ महीने पहले हेरोइन तस्करी के आरोप में गिरफ्तार हुआ था**

- जमानत पर छूटते ही फिर से नरेंद्र सिंह ने हेरोइन तस्करी का काम शुरू कर दिया**

- नरेंद्र सिंह अपने मामा के लड़के बलजीत सिंह को पंजाब से हेरोइन लाने के लिए साथ रखा था**

दौरान इनकी जेब से हेरोइन बरामद हुई। एनसीबी के अनुसार आरोपियों से बरामद हेरोइन की कीमत करीब 72.50 लाख रुपए है। गिरफ्तार करने वाली टीम में एसआई जयवीर, कांस्टेबल बिरेंद्र, मनोज शामिल थे। इस कार्रवाई में डीएसटी टीम के इंचाब रामबिलास, कांस्टेबल हबीब खां, निर्मल बिशोई, पवन, प्रमोद व अश्व नी का विशेष योगदान रहा। आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर जांच सदर थाना के एसआई हंसराज को सौंपी गई है। एसआई हंसराज ने बताया कि आरोपियों का 6 अगस्त तक का पुलिस रिमांड लिया गया है। इनसे सत्यापन से संबंध में पूछताछ की जा रही है।

पुलिस द्वारा गिरफ्तार आरोपी नरेंद्र सिंह उर्फ लबी सैनी लंबे समय से नशे के कारोबार से जुड़ा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार नरेंद्र सिंह पंजाब से थोक में हेरोइन लाकर श्रीगंगानगर में खुदरा बिक्री करने वालों को सप्लाई करता है। फरवरी माह में भी सदर पुलिस ने नरेंद्र सिंह को हेरोइन सहित गिरफ्तार किया था। जमानत पर छूटते ही आरोपी ने फिर से हेरोइन तस्करी का काम शुरू कर दिया। नरेंद्र सिंह के खिलाफ 2022 में भी श्रीकरणपुर थाना में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। इसके अलावा बीकानेर के बीछवाल थाने में मारपीट का मुकदमा भी दर्ज है।

उधर, बलजीत सिंह उर्फ समना रिस्ते में नरेंद्र सिंह का भाई है। नरेंद्र सिंह अपने मामा के लड़के बलजीत सिंह को पंजाब से हेरोइन लाने के लिए साथ रखा था। पुलिस सूत्रों के अनुसार बलजीत सिंह पहली बार पकड़ में आया है। प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी पंजाब के तरणातारन से हेरोइन लेकर आए थे। इस संबंध में विस्तार से पूछताछ की जा रही है।

चार दिन से न्याय के लिए भटक रही दलित नाबालिग पीड़िता ने फांसी लगाई

- गंभीर हालत में पीड़िता को बांगड़ जिला अस्पताल लाया गया, सीकर रैफर किया**

- 29 जुलाई की रात्रि को दौलतपुरा निवासी गीता देवी और उसकी पुत्रियों पर हमला हुआ था**

- थाने से लेकर एसपी ऑफिस तक चक्कर काटने के बाद भी पीड़ित परिवार की नहीं हुई सुनवाई**

होसले बुलंद है और लगातार धर्मकियां दे रहे हैं। इस मामले में कार्रवाई की मांग को लेकर पीड़ित महिला गीता देवी चार दिनों से पुलिस थाना और एसपी कार्यालय के चक्कर लगा रही थी उसके बावजूद उसकी सुनवाई नहीं हुई। इसी बीच मारपीट और छेड़छाड़ से आहत होकर दलित परिवार की एक नाबालिग लड़की ने सोमवार को सुबह फांसी लगाकर आत्महत्या का प्रयास किया। इसके बाद गंभीर अवस्था में पीड़िता को बांगड़ जिला अस्पताल लाया गया, जहां से उसे सीकर रेफर कर दिया गया।

इस मामले में दलित परिवार का आरोप है कि रिपोर्ट के बावजूद पुलिस आरोपितों पर कार्रवाई नहीं कर रही है और पीड़ित परिवार पर ही समझौता करने का दबाव बनाया जा रहा है।

पुलिस उपअधीक्षक धरम पूनिया का कहना है कि रिपोर्ट के बाद में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया जा चुका है। आज इसी प्रकरण में छेड़छाड़ का एक अन्य मामला भी दर्ज किया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की जांच जारी है और किसी भी दोषी को बर्खा नहीं जाएगा।

केमिकल से भरा टैंकर पलटा, चालक जिंदा जला

उदयपुर, (निसं)। बड़ाांव थाना क्षेत्र घसियार रोड़ पर अनियंत्रित टैंकर पलट गया, जिससे धमाका होने के बाद आग लग गई। हादसे में चालक की ज़िंद जलने से मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार सोमवार तड़के जिले के बड़ागांव थाना क्षेत्र घसियार के समीप केमिकल से भरा अनियंत्रित टैंकर पलट गया। जिससे धमाका होने के बाद उसमें आग लग गई तथा चालक की मौके पर ज़िंदा जलने से मौत हो गई। इसकी सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंच कर फायर ब्रिगेड को बुलाकर आग पर काबू किया जब तक चालक की मौत हो चुकी थी, जिसे एम्बी चिकित्सायुग मोचरी में रखवा उसकी शिनाख्त देवरग नगर बरार भीम राजसमन्द निवासी धर्मसिंह पुत्र जवानसिंह रावत के रूप में शिनाख्त कर परिजनों को सूचना दी। इस पर हेड कांस्टेबल राजेन्द्र सिंह ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया।

खेत में मिला 522 ग्राम हेरोइन का पैकेट, ढाई करोड़ रुपए बताई जा रही है कीमत

- पैकेट पर छोटे अक्षरों में कुछ लिखा हुआ है और इस पर मिट्टी नहीं लगी है**

- केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू की, खेत में सर्व ऑपरेशन चलाया है**

इस्तेमाल की जाती है। हेरोइन का यह पैकेट हरकीर्तन सिंह मान के खेत में नरमे की फसल के बीच से बरामद हुआ। इस स्थान पर पैकेट मिला, वहां नरमे के पौधे नहीं हैं। शाम को हरकीर्तन सिंह और कुलदीप सिंह पानी की बारी के लिए खेत में गए

थे। उन्होंने खेत में पड़ा पैकेट देखकर गांव में इसकी सूचना दी। शाम करीब छह बजे ग्रामीण बलजीत मान ने बीएसएफ अधिकारियों को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलते ही बीएसएफ के अधिकारी और जवान मौके पर पहुंचे। मटीलीराठान थाना प्रभारी सुभाषचंद्र भी पुलिस टीम के साथ वहां आए। केंद्रीय एजेंसियों के अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। पैकेट मिलने के बाद विभिन्न एजेंसियों ने खेत में सर्व ऑपरेशन चलाया। पैकेट का वजन 522 ग्राम होने के कारण माना जा रहा है कि पाकिस्तानी तस्करी ने छोटे ड्रोन का इस्तेमाल किया होगा। इसी वजह से यह बीएसएफ और अन्य एजेंसियों की नजर में नहीं आया। पैकेट पर मिट्टी न लगी होने से अनुमान है कि तस्करी का यह प्रयास हाल ही में किया गया है।

